

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३
संख्या : ५३७ / ८-३-१७-६५ विविध / १६ टी०सी०
लखनऊ : दिनांक : ०९ जून, २०१७

अधिसूचना

भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-२०१६ के धारा-२० के प्राविधानों के अन्तर्गत रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के औपचारिक गठन होने तक अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन को दिनांक ०१ मई २०१७ से रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में यथा-अभिहित (designate) किये जाने सम्बन्धी शासन की अधिसूचना संख्या : ४०१ / ८-३-१७-६५ विविध / १६ टी०सी०, दिनांक ०३ मई, २०१७ को संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन, जो भी विभाग के प्रमुख के रूप में कार्यरत हों, को दिनांक ०१ मई २०१७ से रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में यथा-अभिहित (designate) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

शिव जनम चौधरी
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

१. प्रमुख सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन।
२. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
३. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।
४. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
५. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
६. आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
७. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
८. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव